EDITORIAL

Stand Firmly to Save the BSNL

The BSNL's financial condition started eroding from year 2004-05 onward and presently its condition is at very alarming stage. The PSU is in actual loss for the last four years and further continuance of the present situation may bring untold sufferings to the employees sooner or the later. As a matter of fact the union had been raising its deep concerns on the condition right from very beginning. The present circumstances have forced and compelled almost all the unions and associations in the company to come together ***and stand jointly to organize struggle to protect the BSNL.***

The present Govt. widely known for quick decision, has done nothing to help the entity. The Telecom Minister made many declarations on the floor of the Parliament but even after lapse of 8 months no financial package has been extended. The BSNL long ago surrendered BWA spectrums but the deposits made to the tune of more than Rs. 6500 crores to Govt. are not being refunded. *The Govt., DoT, on other hand is compelling and forcing the BSNL to pay the license fee Rs. 500/- crores every year. The Govt. is also not at all fair to the BSNL and anxious to starve it with the shortage of materials and equipments.* If the present situation continues the payment of pay and pension revision of employee may be in doldrum. ***Thus a "Do or Die" situation has developed for BSNL workers.***

The unions and associations in Forum decided three phase struggle i.e. Dharna from 6th to 8th January, Parliament March on 25th February and Indefinite strike from 17th March, 2015 to draw the attention of Govt. The employees responded positively the 1st phase of struggle and organized Dharna in the entire country. Full preparations are now on for 25th February Parliament March to draw the attention of Govt. which has no time to meet and respond to the Unions representing lakhs of employees. ***The employees are thus forced to the walls.*** The memorandum containing signatures of one crore people will be sent to Prime Minister to ***"Save BSNL and Save India"*** after receipt from the circles and Districts unions. Despite this if Govt. does not awake Indefinite Strike will commence from 17th March, 2015.

The unions have long ago submitted a charter of demands viz. Refund of BWA spectrum charges, BSNL services be mandatory to Govt. departments like Air India, Procurement of equipments for expansion of services, Assets Transfer to BSNL, Pension contribution on Basic pay and not on actual, compensate loss for rural Telephony, Fill up the vacant Managerial Posts in BSNL, merge BBNL with the BSNL, no subsidiary tower company and no merger of MTNL with BSNL etc.

Today, it is same Govt. which corporatarised the Telecom services in September, 2000 with promise to keep the BSNL financially viable and strong. The Govt. should honour its past commitments as well as the declarations made in both the houses of Parliament. If promises and commitments are not honoured the workers will have no option ***except to go for decisive struggle from 17th March against the apathy of the Govt.***

The Govt. should understand the BSNL employees will never agree for disinvestment and privatisation. *They are fully ready and prepared to make sacrifices to save the BSNL.*

संपादकीय

बीएसएनएल की सुरक्षा हेतु खड़े हों

विगत आठ वर्षों से बीएसएनएल की आर्थिक दशा शनैः शनैः गिरावट की दिशा में अग्रसरित हो रही थी। इस गिरावट पर संघ निरंतर चिंता व्यक्त करती रही है। इस समय कम्पनी पर वित्तीय संकट गहरा गया है। चार वर्षों से कम्पनी हानि में है तथा इस वर्ष भी लगभग 10,000/– करोड़ रूपये की हानि का अनुमान है। *यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कर्मचारियों को कष्टों का सामना करना पड़ेगा।* निगम में कार्यरत सभी संघों, इक्जीक्युटिव सहित, ने स्थिति को सामूहिक संज्ञान लेकर कर्मचारियों से संघर्ष में उतरने का आह्वान किया है।

सरकार, डीओटी, को संघों तथा फोरम ने बहुत समय पूर्व ही मांगों की सूची प्रेषित कर दी है। मंत्रालय को भी प्रतिवेदन भेजे गए है परन्तु संघों से चर्चा की बात तो दूर है *प्रतिवेदनों पर ध्यान भी नहीं दिया गया है।* नवीन सरकार के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् कर्मचारियों को आशा थी कि बीएसएनएल को संकट से उबारने हेतु ठोस कार्यवाही होगी। माननीय संचार मंत्री संसद के दोनों सदनों में आर्थिक पैकेज देने की घोषणाएं की परन्तु स्थिति यथावत ही है। बीएसएनएल ने कुछ सर्किलों के बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की वापसी सरकार को कर दी है। परन्तु बीएसएनएल द्वारा जमा धनराशि रूपया 6500/– करोड़ से अधिक की वापसी डीओटी ने अभी तक नहीं की है। काल्पनिक ऋण के ब्याज की माफी भी नहीं की गई है। सरकार, डीओटी, बीएसएनएल के रूपए की **वापसी नहीं करने के अनेक तर्क प्रस्तुत करता है परन्तु इसके ठीक विपरीत लाइसेंस फीस की वसूली में कोई शिथिलता नहीं होती है। कम्पनी के साथ भेदभाव का रवैया निरंतर जारी है।** धनाभाव के कारण कम्पनी की सेवाओं का विस्तार नहीं हो रहा है। आर्थिक तंगी के कारण सामग्रियों तथा उपकरणों की खरीदारी करने में बीएसएनएल असमर्थ है। इस परिपेक्ष्य में फोरम के संघों ने सरकार से मांगों की सूची में महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि 65,000/–रूपया करोड़ से अधिक बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम प्रभार की वापसी, नेटवर्क विस्तार हेतु आर्थिक सहायता, टावरों की स्थापना, आप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने पर जोर, ग्रामीण क्षेत्र में टेलीफोन सेवा देने से उत्पन्न हानि का मुआवजा, सम्पत्ति का बीएसएनएल को ट्रांसफर, बीएसएनएल में एमटीएनएल का मरजर नहीं, टावर कम्पनी की स्थापना नहीं आदि को सम्मिलित करके समाधान की मांग की है।

मांगों की पूर्ति तथा बीएसएनएल की सुरक्षा हेतु सभी संघों ने एकजुट होकर संघर्ष का बिगुल भी बजा दिया है। प्रथम चरण में तीन दिवसीय धरना 6 से 8 जनवरी, 2015 तक संपूर्ण भारत में आयोजित हो चुका है। ***इसके उपरांत 25 फरवरी को "संसद मार्च" भी प्रस्तावित है जिसमें प्रत्येक सर्किलों से बीएसएनएल कर्मचारी भाग लेंगे तथा इस दिन प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा।*** संघों ने निर्णय लिया है कि कम से कम एक करोड़ जनता द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ ज्ञापन प्रधानमंत्री को सुपुर्द होगा कि वे बीएसएनएल का पुनुर्थान सुनिश्चित करें। यदि सरकार इन सभी पर संज्ञान नहीं लेती है तो ***17 मार्च, 2015 से इक्जीक्युटिव एवं नॉन–एक्जीक्युटिव कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल संगठित करेंगे।*** कम्पनी के सेवाओं का यदि विस्तार नहीं होता, रेवेन्यू में वृद्धि नहीं होती तो इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए कि **कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय होगा। वेतन तथा पेंशन संशोधन सम्भव नहीं होगा। आखिर सरकार कम्पनी के धन की वापसी क्यों नहीं कर रही है।** सरकार बीएसएनएल के साथ भेदभाव का रवैया क्यों अपना रहीं है? एनडीए सरकार ने ही दूरसंचार सेवाओं का वर्ष 2000 में निगमीकरण किया था तथा उस समय संघों से वादा किया था कि निगम की आर्थिक सुदृढ़ता रखना सरकार की जिम्मेदारी होगी। आखिर वर्तमान *सरकार संसद के अंदर तथा बाहर की गई घोषणाओं का सम्मान क्यों नहीं कर रही है?*

बीएसएनएल की सुरक्षा एक महत्वूपर्ण मुद्दा है तथा यह सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निगम कर्मचारियों तथा उनके परिवार की जीविका सरकार की नीति तथा नियत दोनों ही पवित्र नहीं है। ***कर्मचारियों के सम्मुख "करो या मरो" की स्थिति है।*** बीएसएनएल के प्रति सरकार की उदासीनता तथा भेदभाव का रवैया दुःखद है क्योंकि यह सरकार की सामाजिक जिम्मदारियों का भी निर्वाह करती है। सरकार को स्मरण कराना होगा कि किसने गुजरात (भुज), अंडमान निकोबार, उत्तराखंड, जम्मू–कश्मीर में आपदा के समय दूरसंचार सेवा को बहाल किया है।

आईए हम सभी एकजुट होकर खडे हो तथा बीएसएनएल की रक्षा हेतु संघर्ष करें।

सरकार को पूर्णतः भिज्ञ होनी चाहिए कि कर्मचारी बीएसएनएल में पूंजी विनिवेश तथा निजीकरण की प्रक्रिया को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इनके विरूद्ध प्रबल संघर्ष होगा।